

खबर संक्षेप

रोड पर खड़े वाहन 6 तक हटाएं अन्यथा किए जाएंगे राजसात

मण्डला। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद मंडला से मिली जानकारी के अनुसार नगर के व्यस्त मार्ग कलेक्ट्रेट रोड एवं सैयद हैदर रजा मार्ग पर लम्बे समय से पुराने वाहन खड़े हैं। इस संबंध में नगरपालिका से जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि बैगा-बैगी चौरहा से कलेक्ट्रेट रोड एवं योजना भवन के सामने सैयद रजा मार्ग पर खड़े पुराने दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों के मालिक गुरुवार 6 मार्च 2025 प्रातः 8 बजे तक ले जाएं। गुरुवार सुबह 8 बजे के पश्चात वाहनों की राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।

सात बकायादारों को कुर्की पूर्व सूचना वारंट जारी

मण्डला। न्यायालय तहसीलदार मंडला द्वारा तहसील के तीन पंचायतों के सात बकायादारों को कुर्की पूर्व सूचना वारंट जारी किया गया है। न्यायालय तहसीलदार से मिली जानकारी के अनुसार इन बकायादारों पर भू-राजस्व, पंचायत उपकर, शाला उपकर, डायवर्सन, भू-भाटक की राशि बकाया होने पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत धारा 147 (क), 147 (ख), 147 (ख-ख), 147 (ख-ख-ख) एवं 147 (ग) में निहित प्रावधानों के तहत कुर्की पूर्व सूचना वारंट जारी किए गए हैं। बकायादार दीपक इसरानी/गोपाल दास टिकरिया, जगत मरावी पिता गुलाब सिंह टिकरिया, जवाहर सिरवानी/हरदास टिकरिया, अनिल वीरानी/भोजराज देवरीदादर, महेन्द्र पमनानी/नरेश देवरीदादर, मयंक/बाबूलाल साहू कटरा, अरिहंत मेगा स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड मुदुला कालपीवार कटरा को तीन दिवस का समय दिया गया है। निर्धारित समयवाधि में बकाया राशि जमा न किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

तत्कालिक बीआरसी वित्तीय अनियमितताओं के पाये गये दोषी

शिथिलता से हो रही जांच पर कार्यवाही

*** जिला शिक्षा केन्द्र आरोपों के घेरे में।**

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मण्डला द्वारा तत्कालीन बीआरसी मर्वई और बीजाडांडी को वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग भोपाल को भेजी गई शिकायत के आधार पर जारी किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जिला शिक्षा केंद्र मण्डला में छात्रावास संचालन में अनियमितताएँ हुई हैं और तत्कालीन बीआरसी मर्वई तथा बीजाडांडी द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के खाते में राशि वापस नहीं की गई। इसके बाद, इस मामले की जांच प्रारंभ की गई थी, जिसके



परिणामस्वरूप यह गंभीर मामला सामने आया। जांच में यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान शाला प्रबंधन समितियों को दी गई राशि का अधिकांश हिस्सा विभागीय नियमों के विपरीत खर्च किया गया था। जिला पंचायत मण्डला ने इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया था। जांच दल ने अपनी रिपोर्ट जिला शिक्षा केंद्र मण्डला के कार्यालय को सौंपी, जिसमें अनियमितताओं के संबंध में कुछ गंभीर तथ्य सामने आए।

जांच रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020-21 में विकासखंड मर्वई को 18,75,800 रुपये और 2,69,022.77 रुपये की राशि दी गई थी। इस राशि में से 18,06,017.77 रुपये राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल को वापस किए गए, लेकिन 3,38,805 रुपये का दुरुपयोग किया गया। यह राशि विभाग के बैंक खाते में जमा

नहीं की गई, जो कि शासकीय राशि का दुरुपयोग है। इसी तरह, विकासखंड बीजाडांडी को वर्ष 2020-21 में 21,92,748 रुपये और 2021-22 में 10,28,565 रुपये की राशि दी गई थी। कुल मिलाकर यह राशि 32,21,313 रुपये होती है, जिसमें से 27,51,513 रुपये वापस किए गए, जबकि 4,69,800 रुपये का दुरुपयोग किया गया और यह राशि विभाग के बैंक खाते में जमा नहीं की गई।

इस मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत कटावर्ग की श्रेणी में आते हैं। इन आरोपों के आधार पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई है। साथ ही, चेतावनी जारी करते हुए इन अधिकारियों को तीन दिन के भीतर अपनी सफाई प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यदि निर्धारित समय सीमा में उनका जवाब नहीं मिलता, तो एकतरफा निर्णय लेकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

यह कदम शासन द्वारा निर्धारित

आयुक्त आदिवासी विकास के पास भेजी गई जांच रिपोर्ट के बाद, यह बताया जा रहा है कि पुनः जांच की आवश्यकता है साथ ही फाइल डीपीसी से अभिमत हेतु जिला शिक्षा केंद्र भेजी गयी है। इससे यह प्रतीत होता है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में, यह जरूरी है कि इन वित्तीय अनियमितताओं पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जाए, ताकि सरकारी धन का सही तरीके से उपयोग हो और संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जा सके।

इस मामले में अधिक गंभीरता से जांच की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी अनियमितताएँ न हों और शासन के निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। इसके अलावा, यह भी महत्वपूर्ण है कि अन्य उच्च अधिकारियों और जिला शिक्षा केंद्र के कर्मचारियों को इस जांच के दायरे में लाकर मामले को पूरी तरह से स्पष्ट किया जाए।

यह कार्यवाही शासन द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत की जा रही है, ताकि दोषी अधिकारियों को दंडित किया जा सके और वित्तीय अनियमितताओं से जनता का धन बचाया जा सके।

इनका कहना है :-

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग से उक्त प्रकरण की जांच रिपोर्ट मेरे अभिमत हेतु इस कार्यालय को भेजी गयी है, जल्द ही मेरे अपना अभिमत सहायक आयुक्त को भेजूंगा। ताकि अग्रिम कार्यवाही हो सके।

-अरविंद विश्वकर्मा, डीपीसी, मण्डला

टिकरिया थाने में शांति समिति बैठक हुई संपन्न

हरिभूमि न्यूज | मण्डला/नारायणगंज

जनपद पंचायत नारायणगंज के थाना टिकरिया में शांति समिति की बैठक बुलाई गई जिसमें मार्च में होली गुड़ी पावड़ा एवं रमजान माह संबंधी बैठक बुलाई गई टी आई गोपाल घोसले ने कहा की होली का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने एवं आसपास क्षेत्र में बाहर से आए हुए व्यक्ति की जानकारी थाने में देवें होली में असाभाजिक तत्वों के द्वारा उपद्रव एवं बोर्ड परीक्षा में डीजे का प्रतिबंध लगाया गया जो भी व्यक्ति रात्रि में डीजे का उपयोग करेगा उसे पर सख्त



कार्रवाई की जाएगी बैठक में पहुंचे लोगों ने बस स्टैंड में अवस्था की जानकारी तहसीलदार को दी जिसमें

उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जावेगी शांति समिति बैठक में टीआई गोपाल घोसले तहसीलदार नितिन गोड़ रतन सिंह ठाकुर मंडल अध्यक्ष किशन तेकाम राजेश सोनी गया चक्रवर्ती विपिन छत्रपाल सोनी बलराम साहू महाताब रहीम भाई जान पत्रकार मनोज सोनी राजेश सोनी बंटी सिंगरौर जिला पंचायत सदस्य भूपेंद्र आसपास सरपंचों में अर्जुन सिंह चंदेहरा पंचायत के सरपंच फूलालाबाई ग्राम पंचायत कुड़ामैली के ग्राम पंचायत मानेगांव के सरपंच एवं आसपास की सभी सरपंच शांति समिति बैठक में उपस्थित हुए।

उन्होंने शीघ्र ही कार्यवाही करने के लिए कहा जो भी इस कार्यालय कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करेगा

निर्देश | जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में कलेक्टर ने दिये निर्देश।

शेष लक्ष्य 15 मार्च तक पूर्ण करें-कलेक्टर

*** हितवाही मूलक योजनाओं की हुई समीक्षा।**

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें रोजगारमूलक योजनाओं, किसान क्रेडिट कार्ड तथा बैंक लिंकेज आदि पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। जिला योजना भवन में संपन्न हुई इस बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेंयांश कूमट, एलडीएम सुजय कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधक (एलडीओ) श्री विनय मोरे, जिला प्रबंधक नाबाई देवब्रत पाल सहित संबंधित विभागों के प्रमुख एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित रहे।



इस अवसर पर कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कहा कि सभी विभाग अपनी योजनाओं के शेष लक्ष्य 15 मार्च तक पूर्ण करें। सभी संबंधित अधिकारी बैंक शाखा में योजना के लंबित प्रत्येक प्रकरण की पूरी डीटेल रखें और स्वयं फॉलोअप करें। सभी बैंक अपनी शाखावार आगामी वित्त वर्ष के लिए अपना एनुअल क्रेडिट प्लान बनाकर एलडीएम को सबमिट करें। रोजगारमूलक योजनाओं के

प्रकरणों में बैंकसं सकारात्मक रूख अपनाते हुए उन्हें नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप स्वरोजगार संबंधी योजनाओं के तहत प्राप्त प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान करते हुए उनमें ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रकरणों के फॉलोअप करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं, एसएचजी लिंकेज,

किसान क्रेडिट कार्ड, स्वनिधि योजना, उद्यम क्रांति योजना, बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, आचार्य विद्यासागर योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना आदि के संबंध में विस्तार से समीक्षा की।

सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों पर ध्यान दें बैंक के जिला समन्वयक
बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रेंयांश कूमट ने कहा कि बैंकों के जिला समन्वयक सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों पर ध्यान दें। प्रत्येक शिकायत पर 7 दिवस में रिप्लाई करें। कोई भी प्रकरण नान अटेंडेंट श्रेणी में न रहे। शिकायतों के संतुष्टिपूर्वक निवारण के प्रयास करें। ब्रांच मैनेजर्स आगामी 8 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए तैयारियाँ सुनिश्चित करें। प्रत्येक शाखा अपने-अपने सर्विस एरिया में फाईनेंसियल लिटरेसी कैम्प भी आयोजित कराएँ।



नवीन निजी नलकूपों के खनन पर 31 जुलाई 2025 तक प्रतिबंध

*** ग्रीष्मकाल में संभावित पेयजल संकट के मद्देनजर जारी किया गया आदेश।**

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा ने ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट की संभावना को देखते हुये नवीन निजी नलकूपों के खनन पर 31 जुलाई 2025 तक प्रतिबंध लगा दिया है। जिला दण्डाधिकारी जिला मण्डला मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा-3 के अंतर्गत मण्डला जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। जिले में निरंतर भू-जल की गिरावट को दृष्टिगत रखते हुये अधिनियम की धारा-6(1) के अंतर्गत सम्पूर्ण जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मण्डला जिले की सीमा क्षेत्र की सीमा में नलकूप/बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना न तो प्रवेश करेगी (सार्वजनिक सडकों से गुजरने वाली मशीनों को छोड़कर) और न ही बिना अनुमति के कोई नया नलकूप खनन किया जाएगा।

प्रत्येक राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीनों जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगी अथवा नलकूप खनन/बोरिंग का प्रयास कर रही है, ऐसी मशीनों को जप्त कर में एक.आई.आर. दर्ज कराने का अधिकार होगा। समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके क्षेत्रान्तर्गत इस निमित्त अपरिहार्य प्रकरणों के लिए व अन्य प्रयोजनों हेतु उचित जांच के पश्चात अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत किया गया है। इस अधिसूचना का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा-9 के अनुसार दो वर्ष तक के कारावास या दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है। उपरोक्त आदेश शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले नलकूप उत्खनन पर लागू नहीं होगा तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्ययोजनान्तर्गत नलकूप खनन का कार्य कराया जा सकेगा, इस हेतु उपरोक्तानुसार अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं होगा। नवीन खनित निजी नलकूप एवं अन्य विद्यमान निजी जलस्रोतों का आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत अधिग्रहण किया जा सकेगा। यह आदेश 4 मार्च 2025 से लागू होगा और 31 जुलाई 2025 तक प्रभावशील रहेगा।

आवासीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू

नारायणगंज। एकलव्य आदर्श आवासीय ए विद्यालय नारायणगंज में सीबीएससी पाठ्यक्रम इंग्लिश मीडियम सत्र 2025 26 में अनुसूचित जनजाति छात्रों को कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए 12 सीट बालकों 12 सेट बालिकाओं के लिए उपलब्ध है प्रवेश के लिए ऑनलाइन पर आवेदन कर सकते हैं आवेदन की प्रारंभिक तिथि 18 फरवरी अंतिम तिथि 10 मार्च 2025 एवं प्रवेश पर डाउनलोड करने की प्रारंभिक तिथि 12 मार्च तथा प्रवेश परीक्षा की तिथि 30 मार्च है प्रिंसिपल मनोज कुमार द्वारा बताया गया समय पर आवेदन जमा कर एवं तिथि पर ध्यान रखते हुए आवेदन करें।

हरिभूमि

समाचार ही नहीं, विचार भी

अब हर माह आप बनेंगे भाग्यशाली विजेता

महाबम्पर ड्रॉ में शामिल होने का सुनहरा अवसर

प्रथम पुरस्कार

1 तोला, 5 नग सोने का हार

द्वितीय पुरस्कार

1 स्कूटी (EV)

तृतीय पुरस्कार

2 नग रेफ्रिजरेटर

चतुर्थ पुरस्कार

3 नग LED TV

सांतवना पुरस्कार

1100

नियम व शर्तें :- 1. हर माह जन्मदिन उत्सव फॉर्मेट प्रकाशित किया जायेगा। योजना में भाग लेने के लिए पाठकों को हरिभूमि में प्रकाशित फॉर्मेट को भरकर हरिभूमि कार्यालय, व्यूरो कार्यालय या अपने एजेंट/एजेंसी के पास जमा कर सकते हैं। 2. हरिभूमि के नये एवं पुराने पाठक इसमें भाग ले सकते हैं, जन्मदिन के फॉर्मेट एक माह पहले भेजाये जायेगे, उनके जन्मदिन पर उन्हें सुनिश्चित उपहार दिया जायेगा। 3. प्राप्त जन्मदिन के फॉर्मेट को एकत्रित कर महाबम्पर ड्रॉ में शामिल किया जायेगा जिसका ड्रॉ नवम्बर 2025 में किया जायेगा। 4. जन्मदिन फॉर्मेट के साथ आचार्य का जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ 3 माह उत्सवार का मासिक वित्त लगाना अनिवार्य होगा। 5. जन्मदिन फॉर्मेट की फोटो कापी मान्य नहीं होगी। 6. टाइटल सटकार एवं केन्द्र सटकार के सभी नियम लागू होंगे। इस योजना के विजेता को आयकर के नियम व शर्तें मान्य होंगी। हरिभूमि निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। किसी प्रकार के विवाद में न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा। हरिभूमि कर्मचारी, एजेंट व उनके परिवार के सदस्य इस योजना के पात्र नहीं हो सकते। 7. विषय में दस्तावेज एवं उपहार भिन्न हो सकते हैं।



खबर संक्षेप

शहर के वीरान इलाकों से लेकर सड़क किनारे संचालित हो रही ढाबों में देर रात तक छलकते शांति व्यवस्था को लगा रहे ग्रहण..

गाइरवारा। जहां पूर्व के समय में लोग शराब पीने के लिए ऐसी जगह खोजते थे जहां पर किसी की नजर न पड़े मगर इस समय तो स्थिति इस प्रकार से देखने मिल रही है कि लोगों द्वारा जहां तहां बैठकर शराब का सेवन करते हुए नशे की हालत में सड़कों पर घूमते हुए आसानी से देख जा सकता है? इतना ही नहीं यदि गौर किया जावे तो वर्तमान में अनुमानतः शहर के 60 प्रतिशत युवाओं और किशोरों में शराब पीने का शौक ऐसा लगा है कि वे रात को बिना जाम छलकाये रह ही नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते वे शहर में एक भी वीयरवार न होने और अधिकांश शहर में बने हुये ढाबों में शराब के जाम छलकाने के लिए उपयुक्त जगहों पर जाना पड़ता है पड़ता है और खुलेआम नगर के पास पास बने हुये ढाबों में देर रात तक शराब खोरी होते हुये दिखाई दे रही है? बताया जाता है कि इन दिनों शराब के शौकियों द्वारा नगर के वायुमय मांग पर स्थित ढाबों में जहां खुलेआम शराब की विक्री होने के साथ साथ यहां पर देर रात तक शराब पीने वालों की महफिले सजी हुई देखी जा रही है? इतना ही नहीं हालत यह बन चुकी है कि शहर से चंद कदम दूरी पर संचालित होने वाले इन ढाबों में अवैध रूप से बिकने वाली शराब व देर रात के होने वाली शराब खोरी के चलते जहां क्षेत्र के गांवों के लोगों का शहर आना मुश्किल होते हुये जान पड़ रहा है तो दूसरी ओर रात के समय टेंटों से उत्तरकर अपने गांव जाने वाले लोग भी अपने आपको असुरक्षित महसूस करने से नहीं चूक रहे है? क्षेत्रवासियों द्वारा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा शहर के आसपास संचालित होने वाले ढाबो पर चलने वाले शराब के अवैध कारोबार पर सख्ती से अंकुश लगाने की मांग की जा रही है।

वया कमी इन नहरे में जल बहते हुये देखने का सौभाग्य मिल पायेगा...?

कौड़िया। इस समय देखा जा रहा है कि क्षेत्र का किसान नहीं मिल पाने के कारण अपनी फसलों को लेकर परेशान देखे जा रहे है। वहीं दूसरी ओर स्थिति इस प्रकार से है कि वह आगामी फसलों की तैयारियों को लेकर पानी की व्यवस्था तक पूरी करने में असमर्थ महसूस करने से नहीं चूक रहे है, मगर वहीं दूसरी ओर गौर किया जावे तो क्षेत्र में जहां शासन द्वारा करोड़ो रूपया खर्च करते हुए क्षेत्र के किसानों के खेतों में से नहरों का निर्माण तो कर दिया गया है, मगर उन नहरों में जरूरत के समय पानी नहीं आने के कारण उनके आँचल्य पर भी सबाल खड़े होने लगे है, गौर किया जावे तो जब क्षेत्र में नहरों के निर्माण कार्य की शुरूआत हुई थी उस समय क्षेत्र के किसानों के चेहरों में इस सोच के साथ खुशी झलक रही थी कि क्षेत्र में नहरों का निर्माण होने के कारण उनकी जिन्दगी संभल जावेगी? जब नहरों से पानी आवेगा तो वह अपने खेतों में भर पूर फसल लेते हुए खुशहाली से झूम उठेंगे, मगर इस समय वह खुशी उनके लिए मात्र एक सपना ही साबित हुए जान पड़ रही है..? क्योंकि क्षेत्र में बनी हुई नहरें मात्र उन्हें चिढाते हुए जान पड़ रही है। हालांकि क्योंकि क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बनी हुई नहरों में पानी नहीं छोड़े जाने के कारण लोगों कहे रहे है कि आखिर में जब नहरें बन ही चुकी है तो फिर इसका लाभ क्षेत्र के किसानों को मिल क्यों नहीं रहा है क्या यह नहरें सिर्फ दिखाने के लिए ही बनाई गई थी? जो आज मुश्किल के समय किसानों को उपयोगी साबित नहीं हो रही है तो फिर इनके निर्माण का मतलब ही क्या रह गया है, वहीं दूसरी ओर गौर किया जावे तो नहरों के निर्माण के बाद संबंधित विभाग द्वारा न तो इनकी सफाई की ओर किसी प्रकार से ध्यान दिया गया है और न ही उन्हें चालू किये जाने की ओर कोई पहल की जा रही है, जिसके चलते उनकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ देखा जा रहा है? क्षेत्र के किसानों का कहना है कि यदि समय रहते हुए इन नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया तो इसके खिलाफ क्षेत्र के लोगों द्वारा आंदोलन जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिसके जिम्मेदार नहर विभाग के अधिकारी व नेतागण होंगे।

सरकार की योजनायें दिखाई दे रही है फेल...?



गाइरवारा

इसे माँ नर्मदा की कृपा का फल ही माना जाय कि शहर एवं क्षेत्र के गाँवों में वर्ष भर लोगों को भरपूर पानी नसीब होता रहता है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो गाँवों में भी नल जल योजना के तहत बनीं पानी की टँकियों के निर्माण होने से ग्रामो के निवासियों को कम ही पानी के लिए हायतौबा मचाने विवश होना पड़ता है..? लेकिन जिस तरह विवाह के बाद दूल्हे की मौर नदी में विसर्जित कर उसे भुला दिया जाता है। उसी तरह इस समय देखा जा रहा है कि लगता है शासन-प्रशासन के साथ क्षेत्रवासियों ने उन प्राचीन कुओं, तालाब व बावड़ियों की सुध बिसरना शुरू कर दिया गया है। इसी का परिणाम है कि वर्षों पूर्व प्यासे हजारों कंठ तृप्त होते रहे है वह जन स्रोत आज बदहाली का शिकार होते हुये देखे जा रहे है। ज्ञातव्य है कि नगर ही नहीं क्षेत्र के कई गाँवों में परम्परागत जल स्रोतों की उपेक्षा होने से उनका नामो निशान लगातार मिटता चला जा रहा है..? हकीकत यह है कि जनपद पंचायत साईंखेड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देवरी मिट्ठवानी का लगभग ढाई एकड़ भूमि का मालिक माने जाने वाले



विशाल तालाब अतिक्रमण की भेंट चढ़ने के कारण एक तलैया के रूप में दिखाई देने लगा है। वहीं दूसरी कुछ इसी प्रकार का हाल गाँव के वर्षों पुराने कुँआ का देखने मिल रहा है जिस पर लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करते हुये उसके ऊपर लकड़ी रखते हुये गंदगी फैलाई जा रही है या फिर मवेशियों को बांधते हुये उसकी सुन्दरता को ग्रहण लगाने से भी नहीं चूक पा रहे है जिसके चलते इस प्रकार से वर्षों पुराने पूव्यनीय माने जाने वाले यह परम्परागत स्रोत अपने अस्तित्व को बचाने के लिये खुदे ही जूझते हुये देखे जा रहे है? उल्लेखनीय है कि क्षेत्र के अनुभवी बुजुर्ग अभी भी चाहते है कि कुँआ व तालाब सलामत रहे । मगर विडम्बना की बात है कि प्रशासन के साथ साथ स्वयं सेवी संस्थाएँ पारंपारिक जल स्रोतों की सुरक्षा के मामले में उदासीन बनी हुई है? इस संबंध में हरिभूमि टीम से चर्चा करते हुए क्षेत्र के युवाओं का कहना है कि पर्याप्त पानी मिलने के दौरे में यह बात चिंता जनक है कि पारंपारिक जल स्रोतों की तरफ ध्यान न दिया जा रहा है। वहीं दूसरी देखा जा रहा है कि सरकार द्वारा हर साल करोड़ों रूपया खर्च करते हुये गांव गांव सरोबर से लेकर तालाब व डेमों



का निर्माण कराते हुये रूपया खर्च किये जा रहे है। मगर जिस तरह पुराने जल स्रोत है उनकी अनदेखी सरकार की योजनाओं पर सबाल खड़े करने से नहीं चूक रही है। क्योंकि सरकार द्वारा बनाये जाने वाले तालाबों की सच्चाई शायद ही किसी से छिपी नहीं होगी फ़क़ सरकार द्वारा लाखों रूपया खर्च करते हुये गांव गांव बनाये जा रहे इन तालाबों में एक बूंद पानी नजर आ जावे तो बड़ी बात होने से नहीं चूक पायेगी..? क्योंकि इस तरह नये तालाबों के निर्माण को लेकर सरकार द्वारा जहां करोड़ो रूपया खर्च किये जा रहे है और दूसरी ओर पुराने जल स्रोतों की अनदेखी निश्चित तौर से सरकार के प्रयास मात्र सरकारी धन की होली खेलने के आलवा ओर कुछ साबित होने से नहीं चूक रहे है। यदि वर्तमान में देखा जावे तो जरूरत इस बात की है कि इन परम्परागत जल स्रोतों को चिन्हित कर इनकी दशा में बदलाव लाने की पहल करना अति जरूरी हो गया है। क्योंकि इस प्रकार से पारंपारिक जल स्रोत के अनदेखी करना पूर्णरूप से अनुचित है..? मगर जिस प्रकार से शासन प्रशासन से लेकर क्षेत्र के लोगों द्वारा इन पुराने जल स्रोत की अनदेखी कर रहे है, वहीं लोगों द्वारा अन्य जल स्रोतों को

प्रदूषित करने से भी नहीं चूक रहे है। इस बात की सच्चाई इस समय ग्राम के कुँआ में देखने मिल रही है इस वर्षों पुराने के में आज भी पानी है मगर उसकी ओर प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिये जाने के कारण वह पानी गंदा हो चुका है। यदि इस कुँआ में सुधार किया जावे तो यह क्षेत्र की धरोहर माने जाने वाले परम्परागत जल स्रोतों की फिर से सूरत बदली जा सकती है और वह आमजन के लिये उपयोगी साबित हो सकते है? यदि शासन के रिकार्ड का अवलोकन किया जावे तो क्षेत्र का शायद ही ऐसा कोई गांव शोष होगा जहां पर राजस्व रिकार्ड में तालाब या कुँआ दर्ज दिखाई न दे रहा हो..? मगर बडे ही हैरत की बात है कि सरकारी रिकार्ड के अनुसार राजस्व भूमि पर बने हुये यह कुँआ व तालाब मौके पर नजर ही नहीं आ रहे है जहां तालाबों में प्रभावशालियों की फसले लह लहा रही है तो कुँआ के ऊपर निर्माण कार्य हो चुके है जिन पर बहुमंजिला आवास बने हुये दिखाई देने से नहीं चूक रहे है। इसी प्रकार का हाल नगर में भी आसानी से देखने मिल सकता है। बताया जाता है कि नगर के नाजूक की भूमि पर बने हुये कुँआ का हाल तो यह बना चुका है फ़ि उन पर कुछ प्रभावशालियों द्वारा अतिक्रमण करते हुये अपने आसियाने तानते हुये उनका नामों निशान ही मिटा डाला है..? सरकार द्वारा जिस तरह जल स्रोतों की चिंता करते हुये गांव गांव अमृत सरोबर का निर्माण कराये जाने की जो औपचारिता निर्भाई जा रहे है वह चर्चा का विषय बनने के साथ साथ पंचायतों के प्लये दुधारू गाय के रूप में साबित होने से नहीं चूक रही है..? यदि सच्चाई पर नजर डाली जावे तो बीते हुये वर्षों में जिन ग्राम पंचायतों में अमृत सरोबर के नाम पर लाखों रूपया खर्च करते हुये जिन तालाबों का निर्माण हुआ है उनकी सच्चाई इस तरह देखने मिल रही है कि यदि आज के समय में उनमें एक बूंद पानी नजर आ जावे तो बड़ी बात होगी..?

टूटी हुई लाईन से प्रतिदिन कई गेलन पानी देखने मिल रही बर्बादी, क्या इस सच्चाई के बीच नया जल संरक्षण को सफल बना पायेगी..?

गाइरवारा। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरह जमीन के अंदर जल स्तर में गिरावट देखने मिल रही है वह चिंता की बात है..? यदि इसी तरह जल के स्तर में गिरावट बनी रही तो निश्चित तौर से आने वाले समय में पीने के पानी को लेकर लड़ाई होते हुये देखा जाना आम बात बन जावेगी। हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है कि माँ नर्मदाजी के आशीर्वाद के चलते अभी तक लोगों को पीने के पानी को लेकर परेशान होते हुये देखा नहीं गया है। मगर जल की इस तरह बर्बादी होती रही तो निश्चित तौर से वह दिन दूर नहीं जब हम एक एक बूंद पीने के पानी को लेकर परेशान होते हुये देखे जावेगे। इसी सोच के चलते बीते हुये प्दनों स्थानीय नगर पालिका प्रशासन द्वारा नगर में लोगों को सख्त आदेश जारी करते हुये कहा गया है कि जिन लोगों के घरों में नल



लगे हुये है और उनमें टोटी नहीं होने से पानी बर्बाद हो रहा है वह अपने नलों में टोटी लग जाये। वहीं दूसरी ओर लोगों को इस बात का आदेश भी दिया गया है कि लोग अपने घरों के सामने बगीर मतलब के सड़को तथा वाहनों की धुलाई करते हुये जल की बर्बादी न करे। यदि इस तरह जल को बर्बाद करते हुये कोई पाया ताजा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावेगी। इसके लिये एक टीम का गठन भी किये जाने की खबर है..? जल की बर्बादी पर अंकुश लगाने की सोच के तहत नगर पालिका द्वारा जारी किये गये इस

आदेश की लोगों द्वारा सराहना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मगर जिस तरह नगर पालिका द्वारा जल सप्लाई किये जाने वाली खुद की टूटी हुई लाईनों से प्रतिदिन सैकड़ों गेलान पानी बर्बाद होते हुये देखा जा रहा है। इस सच्चाई को देखते हुये लोग यह बात कहने से नहीं चूक रहे है कि क्या नगर पालिका प्रशासन खुद की लाईनों से इस तरह जल ही जीवने है का नगर देते हुये जल संरक्षण अभियान को सफल बनाने में कामयाब हो

पायेगा..? इस तरह जल बर्बादी के नजारे नगर के भावा वार्ड यानि की विजय कालोनी वार्ड पार्श्व के निवास से चंद कदम दूरी पर देखने मिल रहा है। बताया जाता है कि बीते हुये कुछ प्दनों से कुल्पी वाले साहू जी के मकान वाली कुलिया में देखने मिल रहा है। यहां पर कुछ दिनों से पाईप लाईन में गड़बड़ी होने के कारण प्रतिदिन सैकड़ों गेलान पानी सड़क पर बहने के चलते बारिश के दिनों का यादे ताजा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इस सच्चाई को यहां से फ़कलने वाले लोगों के साथ साथ वार्ड पार्श्व भी देखकर फ़कलने से नहीं चूक रहे होंगे। मगर सुधार न हो पाना निश्चित ही नया जल संरक्षण अभियान की सच्चाई पर सबाल खंडे करने से नहीं चूक रहा है।

दुल्हा राजा अपनी दुल्हनियाँ को लेने पहुंचा हारवेस्टर पर सवार होकर मंडप, नगर में आयोजित हुई यह अनोखी शादी बनी चर्चा का विषय..

गाइरवारा। शादी समारोहों में होने वाली फिजूल खर्च पर अंकुश लगाने के लिये जहां सभी समाजे अपने स्तर पर अंकुश लगाने के लिये प्रयास करते हुये देखी जा रही है। मगर वर्तमान समय में जिस तरह युवा पीढ़ी में बढ़ते हुये शौक समाज के प्रयासों पर ग्रहण लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे है..? अक्सर देखा जाता है कि जब दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिये बारात लेकर जाता है तो पुरानी परम्पराओं के हनुसार हाथी व घोड़े पर सवार होकर जाते थे। इसके बाद लोगों को महंगी नई चमचमाली गाड़ियों पर जाते हुये देखा जाने लगा। मगर बीते हुये दिवस जिस तरह एक दुल्हा को हार वेस्टर पर सवार होकर बारात लगाते हुये देखा गया तो वह चर्चा का विषय बनने से नहीं चूक पाया। यह सच्चाई बीते हुये दिवस नगर में उस समय देखने मिली जब दुल्हा



हार वेस्टर पर सवार होकर अपनी दुल्हनिया को लेने मंडप में पहुंचा। बताया जाता है कि नगर के जमाड़ा रोड स्थित वृद्धवन गार्डन में बीते हुये 2 मार्च को एक शादी समारोह का आयोजन था। इस तरह शाम के समय जब बारात लगने की शुरूआत हुई तो दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिये जब हारवेस्टर पर सवार होकर खुले हुये दुल्हा की हारवेस्टर को चलाते हुये रवाना हुआ तो लोगों का

इस नजारे को देखने के लिये सड़क पर हनुम लगा हुआ दिखाई देने से नहीं चुका। वहीं दूसरी ओर बारात में अनेक प्रकार के डीजे बैंड बाजों सहित विभिन्न प्रकार की लाइटिंगों से सजी हुई बारात के बीच जब लोगों ने दुल्हा राजा का बारात लगाने के दौरान हार वेस्टर पर सवार होकर जाते हुये देखा तो यह शादी समारोह चर्चा का विषय बनने से नहीं चूक पाया है...?

ग्रामीण क्षेत्रों में चालू कम, बंद ज्यादा पड़ी हुई नलजल योजनायें, शोभा की सुपारी साबित हो रही लाखों की राशि से बनी टंकी

कल्याणपुर। शासन प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा की दृष्टि से भले ही नल-जल योजनाओं का गांव गांव शुभारंभ किया जा रहा हो जिसके चलते सरकार का प्रतिवर्ष करोड़ों रूपया भी पानी के नाम पर पानी की तरह ही बहते हुए देखा जा रहा है। लेकिन इन योजनाओं का ग्रामीणों को समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके सच्चाई क्षेत्र की अनेक पंचायतों में देखने आसानी से मिल सकती है, क्योंकि सरकार द्वारा पूर्व में लाखों रूपया खर्च करते हुए अनेक पंचायतों में इस नल जल योजना का शुभारंभ तो कर दिया गया था। मगर वह सिर्फ कागजी तक ही सीमित होकर रह चुकी है। क्योंकि क्षेत्र के अनेक पंचायतों में शुभारंभ के कुछ समय बाद से ही यह योजनाएं बंद पड़ी हुई हैं। बताया जाता है कि नलजल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सुविधा के लिए पंचायत स्तर पर शासन प्रशासन द्वारा नल-जल योजना और स्थानीय जल योजना चलाई गई थी, जिसके चलते कई पंचायतों में इन योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया था। लेकिन योजनाओं से ग्रामीणों को कोई खास लाभ नहीं मिल पा रहा है और जल संकट हर तरफ बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीणों को पीने का पानी उपलब्ध कराना है। लेकिन इस योजना के तहत डाली गई लाईनों से पानी सप्लाह में एकाध बार भी पानी सही ढंग से नहीं मिलता है। इतना ही नहीं कई पंचायतों की स्थिति तो इस प्रकार से है कि नलकुप्ओं में बीते लम्बे समय में ताला उटला हुआ है, इस सच्चाई के चलते इस योजना के नाम पर शासन के पैसों की बर्बादी ही जान पड़ रही है? इन योजनाओं के बंद होने का कारण भी



अलग अलग है। कुछ जल स्रोत सूखने, बिजली कनेक्शन कटने तथा अन्य कारणों से बंद हैं। पीएचई विभाग द्वारा इन योजनाओं के शुरू होने के बाद बंद होने पर सूचना मिलने पर भी रूचि न लेकर बंद होने के कारणों को खत्म करने का प्रयास नहीं किया जाता है और न ही दुरुस्तीकरण में कोई रूचि दिखाई जाती है, जिसके चलते आज भी अनेक पंचायतों में ये योजनाएँ बंद पड़ी हुई या फिर होती जा रही हैं। इस योजना को लेकर पीएचई विभाग के अनुसार नल-जल योजना 2 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाती है तथा इस योजना के तहत एक ट्यूबवैल से अनेक नल कनेक्शन पाईप लाईनों में बिछाकर दिये जाते हैं, घरों में कनेक्शन के बाद पानी की सप्लाई पंचायत स्तर से प्रति दिन या फिर वहां पर जैसी पानी की स्थिति होती है के अनुसार की जाती है बदले में पंचायत द्वारा कनेक्शनधारियों से शुल्क भी लिया जाता है। इस प्रकार से एक हजार से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र में स्थल जल योजना संचालित की जाती है। इस योजना में ट्यूबवैल का खनन करके उसी में मोटर पंप लगाकर कई नल लगा दिये जाते हैं और ग्रामीणों को स्पार्ट पर ही पानी दिया जाता है, इस योजना में घरों में कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं, लोगों को ट्यूबवैल पर ही लगे नलों से पानी भरना पड़ता है, इस योजना को नल-जल योजना में गांव की आबादी बढ़ने पर परिवर्तित कर दिया जाता है।

वहीं दूसरी ओर पड़ने से क्षेत्र के किसानों के माथों पर चिता की लकड़ी उमरने लगी है। जिससे किसानों का कहना है कि यदि कुछ दिनों तक और ठंड का सिलसिला इसी तरह रुका रहा तो रबी सीजन की फसलों की बढत पर विपरीत असर पड़ सकता है। क्योंकि इस मौके पर किसानों के खेतों में तैयार हो रही फसलों को की ठंड की आवश्यकता है। मगर चल रहे मार्च माह के शुरूआती दिनों में दिन के समय सूर्यदेव जिस तरह प्रचण्ड होते हुये दिखाई दे रहे है उससे अनुमान है कि अब ठंड शायद वापसी करेगी। यदि ठंड की वापसी नहीं हुई तो निश्चित तौर से गेहू सहित चना की फसलों पर भी विपरीत असर पड़ने की संभावना से इंकार

दलालों का बोलबाला होने से अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहा है नगर का मवेशी बाजार



गाइरवारा। इस समय देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से प्रति रविवार को नगर में लगने वाला मवेशी बाजार सिर्फ जिले में ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों में भी प्रसिद्ध हो चुका है, जिसके चलते प्रत्येक रविवार को यहां पर दूर के व्यापारी पहुंचकर मन पसंद मवेशी खरीदने के लिए आते है। मगर कुछ समय से यह बाजार लगातार दलालों के चंगुल में आ जाने के कारण सीधे साधे व्यापारियों के लिए सिर्फ परेशानी का कारण ही नहीं बल्कि अव्यवस्थाओं का शिकार भी हो रहे है? यदि इस मवेशी बाजार की सच्चाई पर गौर किया जावे तो क्षेत्र के किसान अपने मवेशियों को यहां पर बेचने के लिए लाते है। मगर बाजार में मौजूद दलालों के चलते लोग अपने मवेशी को मन के मुताबिक कीमत पर नहीं बेच पाते है यदि किसी व्यक्ति को

कोई मवेशी खरीदना या बेचना होता है तो वह दलालों के माध्यम से ही खरीद या विक्री करने के लिए मजबूर होता हुआ दिखाई दे रहे है। इस स्थिति के चलते जहां पशु मालिकों को उनका सही दाम नहीं मिल पा रहा है वहीं दूसरी ओर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति दलालों के अनुसार अपने मवेशी की खरीदी या बिक्री नहीं करता है तो दलाल नुमा लोग उन्हें परेशान करने से भी नहीं चूकते है? इस सच्चाई को लेकर जहां यह बाजार अपना अस्तित्व खोते हुए दिखाई देने लगा है। वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि इस बाजार में पुलिस से तैनाती नहीं रहने की स्थिति में कुछ दलाल नुमा लोगों द्वारा खुलेआम पुलिस के नाम पर मवेशी परिवहन करने वाले लोगों से अवैध बसूली करते हुए दिखाई दे रहे है? जिसकी सच्चाई बीते हुए

बाजार में भी देखने मिली है। बताया जाता है कि जहां क्षेत्र के किसान अपने मवेशियों को बेचने के लिए वाहनों के माध्यम से लाते है उन किसानों से भी कुछ लोगों से अपना पुलिस के बीच प्रेम प्रसंग का बास्ता देते हुए पुलिस के नाम पर अवैध बसूली करते हुए आसानी से देखे जा रहे है..? वहीं दूसरी ओर कुछ इस प्रकार के व्यापारी भी है जो बाजार से थोक में बूटे मवेशी खरीदने के बाद उन्हें कसाई घरों ले जाने के लिए उन्हें अपने वाहनों में कूररता पूर्वक भर कर ले जाने से नहीं चूकते है, इस प्रकार के लोगों को कुछ लोगों द्वारा पुलिस से पूरी सुरक्षा का जिम्मा लेने का भरोसा दिलाते हुए उनका नियम विरुद्ध परिवहन कराने से भी नहीं चूक रहे है? पहले देखा जाता था कि जब इस मवेशी बाजार में पुलिस की डियूटी रहती थी तो मवेशियों का अवैध रूप से कूररता पूर्वक परिवहन करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगा हुआ था, मगर अब घोषित रूप से पुलिस की डियूटी नहीं रहने के कारण कुछ दलालों द्वारा इस प्रकार से कूररता पूर्वक पशुओं को ले जाने वालों से पुलिस के नाम पर पैसा बसूलते हुए पुलिस की कार्य प्रणाली पर दाग लगाने से नहीं चूक रहे है? इस प्रकार से प्रति रविवार को देखा जाता है कि नगर के मवेशी बाजार में मवेशियों का क्रय विक्रय करने से लेकर उनका परिवहन कराने का जिम्मा लेने की बात करते हुए खुलेआम अवैध बसूली करते हुए देखे जा रहे है? इसी का परिणाम है कि गाइरवारा क्षेत्र में फिर पशुओं की कूररता पूर्वक परिवहन की गतिविधियाँ नजर आने लगी है तथा शहर सहित क्षेत्र के आसपास अनेक जगहों से पशुओं को खुलेआम वाहनों में कूररता पूर्वक भरा जा रहा है? इस प्रकार से पुलिस के नाम पर दलाल नुमा लोगों द्वारा की जा रही अवैध बसूली की सच्चाई को लेकर पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध बनते हुये नजर आने से नहीं चूक पा रही है?

बादलों के अजीब खेल से किसान चिंतित, चना सहित अन्य फसलों में इल्ली रोग लगने की आशंका

साईंखेड़ा। क्षेत्र के किसान लगातार परेशानियों से जूझते हुये दिखाई पड़ रहे है। क्योंकि बीते हुए कुछ वर्षों से जिस प्रकार प्रकृति का खेल चल रहा है उसके चलते इस बदलते दौर में अब किसी को भी मौसम पर विश्वास नहीं रह गया है। क्योंकि इस वर्ष ठीक तरह से ठंड व पड़ने साथ साथ आसमान में बादलों के अजीब खेल से क्षेत्रीय किसान भी अपनी रबी सीजन की फसलों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आने लगे है। ज्ञातव्य है कि फिलहाल आसमान में आये दिन मंडराने वाले बादल ठंड पर ब्रेक लगा रहे है और दोपहर में लोगों को उमस और रात में थोड़ी ठंड का अहसास हो रहा है। ऐसे में गांव के किसान मौसम को प्रतिकूल मान रहे है तथा फसलों की बढत के लिए तेज ठंड पड़ना आवश्यक बता रहे है। हरिभूमि टीम से चर्चा करते हुए क्षेत्र के किसानों ने कहा कि इस वर्ष जहां बारिश ने किसानों को धोखा देने के बाद जब ठंड ने दस्तक दी थी, तो उसके अंदाज से लगा रहा था कि ठंड की गति संतोष जनक ढंग से रहेगी। किन्तु स्थिति यह देखने मिली की बीते हुये फरवरी माह में अचानक ठंड पर ब्रेक लगने के चलते खेतों में ऊंग रही फसलों की गति पर अंकुश लग गये था। इस तरह बादलों का आसमान में डेरा नहीं हटने के कारण, फसलों को लाभ पहुंचाने



वहीं दूसरी ओर पड़ने से क्षेत्र के किसानों के माथों पर चिता की लकड़ी उमरने लगी है। जिससे किसानों का कहना है कि यदि कुछ दिनों तक और ठंड का सिलसिला इसी तरह रुका रहा तो रबी सीजन की फसलों की बढत पर विपरीत असर पड़ सकता है। क्योंकि इस मौके पर किसानों के खेतों में तैयार हो रही फसलों को की ठंड की आवश्यकता है। मगर चल रहे मार्च माह के शुरूआती दिनों में दिन के समय सूर्यदेव जिस तरह प्रचण्ड होते हुये दिखाई दे रहे है उससे अनुमान है कि अब ठंड शायद वापसी करेगी। यदि ठंड की वापसी नहीं हुई तो निश्चित तौर से गेहू सहित चना की फसलों पर भी विपरीत असर पड़ने की संभावना से इंकार

नहीं किया जा सकता है..? लेकिन इस वर्ष ठंड की शुरूआत तो हुई है मगर आसमान में बादलों के चलते बीते हुये जनवरी व फरवरी माह में अरबी ठंड नहीं पड़ पाई थी जिसके चलते फसलों की प्रगति पर अंकुश लगा रहा और अब दिन के समय तेज तपन के चलते फसलों की स्थिति खराब होते हुये दिखाई दे रही है। क्योंकि खेतों में खड़ी गेहू चना फसल फल चुकी है। मगर अभी से तेज तपन होने के कारण जहां फलों के अंधक बन रही है। वहीं दूसरी ओर आसमान पर छाये हुये बादलों के क्राण्ड इल्ली सहित अन्य प्रकार की कीट जनम लेते हुये दिखाई दे रहे है। इस प्रकार मौसम में गर्मी का होना रबी फसलों के लिए खतर नाक बना हुआ है। इस स्थिति में एक बार फिर क्षेत्र के किसान समस्याओं के जाल में फँसते नजर आ रहे है तथा इस स्थिति में क्षेत्र के किसान भारी परेशानी में पड़ गये है। क्योंकि रबी फसलों की अरबी पैदावार के लिए आने वाले कुछ दिनों तक और ठंड की जरूरत महसूस कर रहे है। इस समय क्षेत्र के किसान मुश्किलों के पहार तो किसी तरह झेल लेता है, मगर मौसम की मार उसके लिए असहनीय होती चली जा रही है।

अपने साथ साथ दूसरों की जिन्दगी को भी पहुंचाते है खतरा, प्रशासन की चुप्पी पर खड़े हो रहे सवाल

हरिभूमि व्यूज/ साईंखेड़ा। जहां एक ओर आये दिन पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात में सुधार लाने की बात को लेकर चालानी कार्यवाही करते हुये देखा जाता है, जिसमें अनेक इस प्रकार के लोगों के खिलाफ भी पुलिस द्वारा अपनी चालानी कार्यवाही करने से नहीं चूकती है जो किसी भूखण्ड अपने वाहनों के जरूरी कागज धरो पर भूल जाते है और उन्हें पुलिस की इस कार्यवाही का शिकार होना पड़ता है? मगर यदि सच्चाई पर गौर किया जावे तो पुलिस द्वारा उन लोगों को पूर्णरूप से नजर अंदाज कर दिया जाता है जो एक बाइक पर तीन की जगह खुलेआम चार चार लोग बैठते हुये जहां यातायात नियमों की धड़ियां तो उठाते हुये देखे ही जाते है साथ ही साथ अपनी व दूसरों की जिन्दगी को खतरा पैदा करने से नहीं चूकते है? इस बात की सच्चाई बीते दिवस नगर के मुख्य बाजार में उस समय देखने मिली जब एक बाईक पर चार लोग बैठते हुये पुलिस थाने के ठीक सामने से निकलकर बाजार तक पहुंच गये पर पुलिस द्वारा इनके खिलाफ कार्यवाही करने की बात तो दूर उन्हें रोकस्ट्र हितायद देना भी जरूरी नहीं समझा। अब सबाल यह पैदा हो रहा है कि यदि इस प्रकार के वाहनों के माध्यम से कोई सड़क घटना घटित हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि इस प्रकार से वाहनों के संचालन को पुलिस प्रशासन द्वारा नजर अंदाज किये जाने का परिणाम है कि वाहन चालक खुद के साथ साथ दूसरों की जिन्दगी को भी खतरा पैदा करने से नहीं चूक रहे है, मगर इसके भी पुलिस द्वारा इस को नजर अंदाज किया जा रहा है।

